समक्ष राजबीर सेहरावत, जे.

टाटा एयर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

राम अवतार और अन्य-2015 के प्रतिवादी एफएओ No.3878

13 दिसंबर, 2017

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-S.166-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948-S.51E, 53 और 61-मुआवजे के अन्य दावों पर रोक जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाता है-माना जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए कोई रोक नहीं है-ईएसआई अधिनियम की खंड 53 द्वारा बनाई गई रोक केवल किसी भी बाद के मुआवजे के संबंध में है यदि घायल या उसके आश्रित द्वारा ईएसआई अधिनियम के तहत एक कर्मचारी होने का दावा किया जाता है-यह केवल नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को श्रम कानून के तहत मुआवजे की प्राप्ति पर रोक लगाता है-ईएसआई अधिनियम की खंड 61 में यह भी कहा गया है कि एक कर्मचारी समान लाभों का हकदार नहीं है-मोटर वाहन अधिनियम और ईएसआई अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई समानता नहीं है। यह कहकर कि एक व्यक्ति के लिए विभिन्न और स्वतन्त्र उपाय उपलब्ध हैं मिश्रित करके मुआवजा देने से मना नहीं किया जा सकता है l आगे, यद्यपि मृतक के आश्रितों द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त की जा रही है, पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है l

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि खंड 51 ई, जिसे अधिनियम में 01.06.2000 जोड़ा गया है, यह काल्पनिक कल्पना पैदा करता है कि किसी कर्मचारी के साथ कर्तव्य का पालन करने के बाद अपने निवास से कर्तव्य के लिए रोजगार के स्थान पर या रोजगार के स्थान से अपने निवास स्थान पर आने-जाने के दौरान होने वाली दुर्घटना को रोजगार के 'बाहर' और 'पाठ्यक्रम' में उत्पन्न माना जाएगा, हालांकि, यह काल्पनिक कल्पना भी इसके संदर्भ में आत्यन्तिक नहीं है।खंड स्वयं यह स्पष्ट करता है कि

कर्मचारी को लगी चोट को 'रोजगार चोट' माना जाएगा, जब वह कार्यस्थल पर आता है या जाता है, केवल तभी जब रोजगार का उन परिस्थितियों, समय और स्थान के साथ संबंध है जिसमें दुर्घटना हुई थी। (पैरा 25)

आगे कहा कि इससे पता चलेगा कि अधिनियम की खंड 53 द्वारा बनाई गई बाधा केवल किसी अन्य अन्य बाद के मुआवजे के संबंध में होगी, यदि घायल या आश्रितों द्वारा दावा किया जाता है; ई. एस. आई. अधिनियम के तहत एक कर्मचारी होने के नाते घायल/मृतक की क्षमता में। इसका मतलब यह होगा कि यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा नहीं है जिसे अधिनियम की खंड 53 द्वारा बाहर रखा जाएगा, बल्कि यह कोई अन्य मुआवजा होगा, यदि दावा किया जाता है, तो किसी अन्य अधिनियम के तहत जिसमें ईएसआई अधिनियम के तहत परिभाषित कर्मचारियों के लिए समान मुआवजे के प्रावधान हैं। इसका मतलब है कि अधिनियम की खंड 53 केवल किसी अन्य श्रम कानून के तहत नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति से मुआवजे की प्राप्ति पर रोक लगाती है जो कर्मचारियों/श्रमिकों को मुआवजा प्रदान कर सकता है।यह अधिनियम की खंड 61 के प्रावधान द्वारा भी स्पष्ट किया गया है; जो विशेष रूप से कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति को ई. एस. आई. अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किया जाता है, तो वह किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य किसी भी 'समान लाभ' को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।अधिनियम की खंड 53 के प्रावधानों की कोई अन्य अप्रतिबंधित व्याख्या करने से अधिनियम की खंड 61 अनावश्यक हो जाएगी।और यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायिका को कानून की किसी भी खंड में व्यर्थ के शब्द नहीं माना जा सकता है, ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 61 की तरह कानून की पूरी खंड को बर्बाद करने की बात करने के लिए बहुत कम है। इसलिए अधिनियम की खंड 61 के साथ पढ़ें, खंड 53 की व्याख्या नियोक्ता से या ई. एस. आई. अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में अपनी क्षमता में ऐसे घायल व्यक्ति/आश्रित को क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक किसी भी व्यक्ति से कर्मचारी के रूप में अपनी क्षमता में समान मुआवजे के केवल दूसरे दावे को प्रतिबंधित करने के लिए की जा सकती है। चूँकि मोटर वाहन अधिनियम और ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध लाभों के बीच कोई समानता नहीं है, इसलिए मोटर वाहन

अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को मुआवजे से इनकार करने के लिए दो अधिनियमों के प्रावधानों को मिलाया नहीं जा सकता है। (पैरा 27)

आगे कहा कि चूंकि परिवार पेंशन प्राप्त करना भी मृतक के आश्रितों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए कोई बाधा नहीं है, इसलिए दुर्घटना से उत्पन्न दावे के खिलाफ किसी अन्य समान आवधिक भुगतान के प्रतिबंध होने का कोई सवाल ही नहीं है। (पैरा 29)

राजेश के शर्मा, अधिवक्ता

अपीलकर्ता के लिए।

तन्मोय गुप्ता, प्रतिवादी नं. 1 के लिए अधिवक्ता

सुरिंदर डागर अधिवक्ता,

उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के लिए l

राजबीर सहरावत, जे. (मौखिक)

(1) यह उल्लंघन करने वाले वाहन की बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई अपील है जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गुड़गांव द्वारा दावा याचिका की स्थिरता और मुआवजे की मात्रा के आधार पर पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जैसा कि भविष्य की संभावनाओं के कारण बढ़ाया गया है।

(2) इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दावा याचिका देवेंद्र कुमार के पिता द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने मोटर वाहन दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी।दावा याचिका में यह दावा किया गया था कि 17.04.2013 पर लगभग 10 बजे:30 पी. एम. देवेंद्र कुमार; सुरेश कुमार और राज कुमार अपनी कंपनी सनबीम ऑटो लिमिटेड, 38/6 किमी स्टोन, दिल्ली-जयपुर, राजमार्ग संख्या 8, नर्सिंगपुर, जिला गुड़गांव में अपनी ड्यूटी के बाद अपने घरों को जा रहे थे।जब वे नितिन विहार, ट्रांसपोर्ट नगर, गुड़गांव के पास हीरो होंडा चौक से थोड़ा आगे पहुंचे तो पंजीकरण संख्या वाला एक ट्रक। एचआर-55 एम-4737 पीछे से आया, जिसे प्रतिवादी नंबर 1 (दावा याचिका में) द्वारा तेज गति से और जल्दबाजी और लापरवाही से और सर्विस रोड पर चलाया जा रहा था।ट्रक ने पीछे से देवेंद्र कुमार और

राज कुमार को टक्कर मार दी।ट्रक के चालक ने उन्हें टक्कर मारने के बाद अपने ट्रक को रोक दिया।सुरेश कुमार और देवेंद्र कुमार के सिर में चोटें आई हैं।वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई और घायलों को एक निजी वाहन में अस्पताल ले जाया गया।इसके बाद आरोपी ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया।हालांकि, दुर्घटना में घायल हुए देवेंद्र कुमार ने दम तोड़ दिया।इसलिए याचिका दायर की गई थी।

(3) याचिका में दावा किया गया था कि मृतक की उम्र लगभग 24 वर्ष थी और वह स्वस्थ था।यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ता के पास अपना भरण-पोषण करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं था और मृतक याचिकाकर्ता का इकलौता बेटा था।यह दावा किया गया था कि मृतक रुपये कमा रहा था। 10, 000/- प्रति माह।इसलिए एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। 20 लाख की मांग की गई।

(4) नोटिस की प्राप्ति पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 उपस्थित हुए और लिखित बयान दायर किया।याचिका की दलीलों को खारिज कर दिया गया।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि उल्लंघन करने वाले वाहन का दावा याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 के साथ बीमा किया गया था और चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।इसलिए, यह दावा किया गया कि किसी भी मामले में, यह प्रतिवादी संख्या 3, उल्लंघन करने वाले वाहन की बीमा कंपनी होगी जिसे मुआवजे का भुगतान करना होगा।

(5) प्रतिवादी संख्या 3, बीमा कंपनी ने नियमित प्रारंभिक आपत्तियां लेते हुए लिखित बयान दायर किया। योग्यता के आधार पर यह दावा किया कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। प्रतिवादी संख्या 3 ने मुआवजे का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार कर दिया। यह दावा किया गया था कि दावेदारों ने प्रतिवादी संख्या 3, बीमा कंपनी से पैसे निकालने के लिए एक झूठी कहानी रची थी।

(6) दलों ने अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया।

(7) मृतक का वेतन प्रमाण पत्र और मस्टर रोल रिकॉर्ड पर साबित हुआ।इसके अलावा दावेदार द्वारा चश्मदीद गवाह से पूछताछ की गई।प्रतिवादी संख्या 1 का ड्राइविंग लाइसेंस, उल्लंघन करने वाले वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ बीमा पॉलिसी को भी रिकॉर्ड में रखा गया था।

(8) दूसरी ओर, प्रतिवादी ने कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया।चालक और मालिक ने चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, उल्लंघन करने वाले वाहन का राष्ट्रीय परमिट, वाहन की बीमा पॉलिसी और वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में रखा।इसके अलावा, प्रतिवादी बीमा कंपनी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (संक्षेप में, 'ई. एस. आई. निगम') से प्राप्त जानकारी भी प्रस्तुत की, जिसमें दिखाया गया है कि ई. एस. आई. निगम द्वारा दावेदार को कुछ भुगतान किया गया है।

(9) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने दावा याचिका को स्वीकार कर लिया।नतीजतन, रुपये की राशि। 9,53,950/- ब्याज के साथ दावेदार को दिया गया था।उल्लंघन करने वाले वाहन की बीमा कंपनी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

(10) मुआवजे के उपरोक्त आंकड़े पर पहुँचते हुए, न्यायाधिकरण ने कहा कि मृतक के वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार उसने रु० 9, 587/- और कुछ कटौती के बाद उनका शुद्ध देय वेतन रु० मार्च, 2013 के लिए 8,858/- प्रति माह।हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि वेतन से की गई कटौती मुआवजे के उद्देश्य से आय के आकलन के लिए कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है।यह भी माना गया कि मृतक की आय पर विवाद करने के लिए प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई अन्य सबूत नहीं है।अतः तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की आय का अनुमान रु। 9000/- प्रति माह।इसके अलावा न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दावेदार मृतक की आय के 50 प्रतिशत तक भविष्य की संभावनाओं का लाभ उठाने का हकदार है।फिर भी मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि मामले में लागू गुणक 18 होगा।न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि चूंकि मृतक कुंवारा था और दावेदार मृतक का पिता है इसलिए मृतक की आय का 50 प्रतिशत उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाना चाहिए। दावेदार को 25,000/- रुपये की राशि अंतिम संस्कार के रूप में खर्चे के लिए भी हकदार ठहराया गया था। 25, 000/- अंतिम संस्कार के खर्च के लिए भी।

(11) इसके अलावा प्रतिवादी बीमा कंपनी/अपीलकर्ता ने यहां एक आपत्ति जताई कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका को कर्मचारी राज्य बीमा

अधिनियम, 1948 की खंड 53 (संक्षेप में, 'ई. एस. आई. अधिनियम') द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि दावेदार ने ई. एस. आई. निगम से भी कुछ लाभ लिए हैं।इस उद्देश्य के लिए, बीमा कंपनी ने ई. एस. आई. निगम के अधिकारियों से प्राप्त कुछ जानकारी पर भरोसा किया था कि दावेदार को उसके बेटे देवेंद्र कुमार की मृत्यु के कारण कुछ भुगतान किया गया था।इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि हालांकि दावा याचिका को स्वयं प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, लेकिन ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत दावेदार द्वारा प्राप्त लाभों में कटौती की जा सकती है।तदनुसार न्यायाधिकरण ने ई. एस. आई. निगम से प्राप्त लाभों की सीमा तक कटौती की।

(12) नतीजतन, हालांकि मृतक की आय रु० 9,000/- प्रति माह।भविष्य की संभावनाओं के कारण 50 प्रतिशत की वृद्धि को जोड़ते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना रु० 9000 + 4500 (9000 x 50/100) = रु० 13, 500/- प्रति माह। इस राशि में से व्यक्तिगत खर्चों के कारण न्यायाधिकरण द्वारा 50 प्रतिशत की कटौती की गई थी।इसलिए मृतक की आय घटाकर 6,750 रुपये कर दी गई।इसमें से न्यायाधिकरण ने एक करोड़ रुपये की राशि भी काट ली, 2,403/- जो ई. एस. आई. निगम द्वारा दावेदार को आवधिक भुगतान के रूप में भुगतान किया जा रहा था।इसलिए सभी परिवर्धन और कटौती करने के बाद न्यायाधिकरण ने मृतक की आय को एक लाख रुपये कर दिया था, 4,347/- 18 के गुणक को लागू करते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दावेदार की निर्भरता के नुकसान की गणना रु० 9,38,952-(4347 x 12 x 18)।

(13) जहाँ तक अंतिम संस्कार के खर्चों का संबंध है, हालाँकि न्यायाधिकरण ने दावेदार को 25,000/- रुपये की राशि का हकदार ठहराया। हालाँकि, अंतिम संस्कार के खर्च के कारण न्यायाधिकरण ने 10,000/- रुपये की कटौती की। इस आधार पर कि मृतक के अंतिम संस्कार पर अंतिम संस्कार के खर्च के लिए ई. एस. आई. अधिकारियों द्वारा 10,000/- रुपये का भुगतान किया गया था।तदनुसार, केवल रु। 15, 000/- दावेदार को देय माना गया था।

(14) तदनुसार, कुल रु० 9,53,952/- जो रु० 9,53,950/- दावेदार को देय माना गया था।

(15) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के इस फैसले के खिलाफ, बीमा कंपनी ने वर्तमान अपील दायर की है। हालाँकि, दावेदार द्वारा राशि बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई है।

(16) अपीलकर्ता के लिए मामले में बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता दो आधारों पर पुरस्कार के खिलाफ व्यथित है, अर्थात्, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 53 द्वारा प्रतिबंधित किए जाने से पहले दावा याचिका स्वयं विचारणीय नहीं थी और इसलिए, इस मामले में न्यायाधिकरण द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता था।दूसरा यह कि भले ही दावा याचिका विचारणीय हो; इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले में दावेदार को निर्धारित आय के 50 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाएं प्रदान नहीं की जा सकती थीं राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम प्रणय सेठी 1 के मामले में अदालत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 50 वर्ष तक के स्व-नियोजित व्यक्ति के मामले में भविष्य की संभावनाओं का लाभ 40 प्रतिशत होगा न कि 50 प्रतिशत की दर से।अपने पहले तर्क का समर्थन करने के लिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। जो राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हमीदा खातून और अन्य 2.के लिए उसी प्रस्ताव विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी भरोसा किया है जिसका शीर्षक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोम वाती और अन्य 3 है जिसमें हमीदा खातून के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का पालन किया गया था।

(17) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मुआवजा अपर्याप्त रूप से दिया गया है।उनके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि दावेदार ने वृद्धि के लिए अपील दायर नहीं की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ई. एस. आई. निगम द्वारा दिए गए लाभों के कारण न्यायाधिकरण द्वारा की गई कटौती गलत तरीके से की गई है।उनका निवेदन है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दावा याचिका

विचारणीय है।ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 53 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत याचिका को बाहर नहीं करती है।इसलिए अपील को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

(18) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 53 के अनुसार दावा याचिका विचारणीय नहीं है, खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी है।सबसे पहले, ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 53 ई. एस. आई. अधिनियम का हिस्सा है। इसलिए यह केवल लागू होगा उस व्यक्तियों या संस्थाओं के संबंध में इस अधिनियम का विस्तार किया गया है या इस अधिनियम की आवेदन खंड और परिभाषा खंड द्वारा लागू किया गया है। इस अधिनियम की खंड I निर्धारित करती है कि यह कारखानों पर लागू होगी।खंड 1 के प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि यह अधिनियम किसी अन्य कारखाने या प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होगा, जिसके कर्मचारियों को इस अधिनियम की तुलना में समान या उच्चतर लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा इस अधिनियम की खंड 2 ए में यह निर्धारित किया गया है कि जिन कारखानों पर यह अधिनियम लागू होता है, उन्हें इस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा। इसके अलावा इस अधिनियम की खंड 2 कर्मचारी और नियोक्ता को परिभाषित करती है जो यह अधिनियम लागू होता है।अतः इन प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि इस अधिनियम का अनुप्रयोग, जिसमें इस अधिनियम की खंड 53 भी शामिल है, कई शर्तों द्वारा सीमित है।अतः इस अधिनियम की खंड 53 सहित ऐसा कोई आवेदन नहीं है जिसमें लाभ प्राप्तकर्ता कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नियोक्ता और कारखाने की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि इस अधिनियम द्वारा दिया गया है और लाभ का दावा किया जाता है और इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में उसे भुगतान किया जाना आवश्यक है। इतना ही नहीं, अधिनियम स्वयं घोषणा करता है कि यह अधिनियम कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा यदि कर्मचारी किसी अन्य अधिनियम के तहत कुछ बेहतर लाभों का हकदार है और कारखाना सरकारी कारखाना या सरकारी नियंत्रित कारखाना है।इसलिए इस अधिनियम की खंड 53 सहित इसे लागू करने के लिए आवश्यक विशेषता यह है कि एक तरफ यह इस अधिनियम के तहत परिभाषित एक

कर्मचारी होना चाहिए और दूसरी तरफ, यह नियोक्ता या कारखाना होना चाहिए जैसा कि इस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, और आगे दावा किया गया लाभ इस अधिनियम के तहत कर्मचारी के रूप में व्यक्ति की क्षमता में होना चाहिए। यदि दावा करने वाले व्यक्ति की क्षमता इस अधिनियम की प्रयोज्यता के दायरे से बाहर है या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस अधिनियम की प्रयोज्यता के दायरे से बाहर है, तो इस अधिनियम की खंड 53 सहित इस अधिनियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है। ऐसा दावा इस अधिनियम की खंड 53 सहित पूरी तरह से लागू होने के दायरे से बाहर होगा।अतः मोटर वाहन अधिनियम की खंड 166 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा दायर दावा याचिका को इस अधिनियम की खंड 53 द्वारा तभी प्रतिबंधित किया जाएगा जब दावा करने वाला व्यक्ति स्वयं बीमा कंपनी का कर्मचारी हो जो मोटर वाहन अधिनियम के अधिनिर्णय को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी हो। यदि दावेदार और बीमा कंपनी के बीच संबंध किसी अजनबी का है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी बीमा कंपनी के खिलाफ दावा याचिका ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 53 द्वारा वर्जित नहीं होगी। खंड 53 में "कोई भी व्यक्ति" शब्द को उस व्यक्ति/संस्था के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसके लिए यह अधिनियम लागू होता है।कोई अन्य व्याख्या देने का अर्थ होगा इस अधिनियम को अन्य सभी अधिनियमों पर एक प्रमुख प्रभाव देना। हालाँकि, विशेष रूप से यह खंड से शुरू होती है कि किसी भी 'गैर-अस्थाई' खंड के साथ और न ही इस अधिनियम की कोई अन्य खंड है जो अन्य अधिनियमों के अलावा अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाती है। इस अधिनियम की खंड 61 किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी कर्मचारी को स्वीकार्य केवल 'समान लाभों' को भी प्रतिबंधित करती है यदि ऐसा कर्मचारी इस अधिनियम के तहत ऐसे लाभों का हकदार है। इसलिए यह खंड एक कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी की चोटों के संबंध में केवल दोगुने 'समान लाभ' प्राप्त करने पर भी रोक लगाती है, इसके अलावा कुछ नहीं।इसलिए केवल इसलिए कि घायल या मृतक के आश्रितों को ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कुछ लाभ मिल रहे हैं, उन्हें किसी अन्य अधिनियम के तहत उपलब्ध किसी अन्य लाभ से वंचित करने का कोई आधार नहीं है, यदि इस तरह के अन्य अधिनियम के तहत उन्हें उपलब्ध लाभ ई. एस. आई. अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभ के समान नहीं हैं। इस अधिनियम की खंड 53 की

कोई अन्य व्याख्या करने से इस अधिनियम की खंड 61 निरर्थक हो जाएगी।इस स्थिति को निम्नलिखित पैराग्राफ द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है।

(19) इसके अलावा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे को ठीक से समझने के लिए, ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 53 को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः

"धारा 53:किसी अन्य कानून के तहत नुकसान के मुआवजे की प्राप्ति या वसूली के खिलाफ रोकः-

एक बीमित व्यक्ति या उसके आश्रित इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में बीमित व्यक्ति को लगी नौकरी की चोट के संबंध में श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 923 (1923 का 8) या किसी अन्य कानून के तहत कोई मुआवजा या नुकसान प्राप्त करने या वसूल करने के हकदार नहीं होंगे।

(20) ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 53 के अवलोकन से पता चलता है कि यह खंड केवल एक निषेधात्मक खंड है न कि किसी भी लाभ की पात्रता से संबंधित खंड। इसलिए इस खंड की व्याख्या ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे और संदर्भ के संदर्भ में की जानी चाहिए। यदि एकल खंड के रूप में पढ़ा जाता है तो यह खंड किसी कर्मचारी या उसके आश्रितों को कहीं से भी किसी भी प्रकार के मुआवजे से वंचित कर देगी।यह पूरी तरह से हास्यास्पद तर्क परिणाम होगा।अतः इस खंड द्वारा बनाए गए निषेध के प्रसार का निर्धारण इस खंड में उपयोग किए गए सीमित शब्दों के साथ-साथ इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे परिभाषा खंड और इस अधिनियम की खंड 61 के संदर्भ में निषेधात्मक व्याख्या देकर किया जाना चाहिए। इसलिए इस खंड के तहत जो वर्जित है वह है घायल या उसके आश्रितों को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम या रोजगार चोट के संबंध में किसी अन्य कानून के तहत कोई मुआवजा या हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार होगा जो घायल/मृत व्यक्ति द्वारा और इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में उसकी क्षमता में। इसलिए यह स्पष्ट है कि खंड 53 द्वारा बनाया गया प्रतिबंध केवल उस स्थिति में लागू होगा जब घायल/मृतक को लगी चोटें नौकरी में लगी चोट हैं और यह चोट घायल/मृतक को कर्मचारी के रूप में लगी है और केवल तभी जब वह इस

अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में अपनी क्षमता में बाद के मुआवजे का दावा कर रहा है।

(21) रोजगार क्षति को ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 2 (8) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> """"रोजगार चोट" का अर्थ है किसी कर्मचारी को दुर्घटना या उसके रोजगार से और उसके दौरान उत्पन्न होने वाली व्यावसायिक बीमारी के कारण व्यक्तिगत चोट, जो एक बीमायोग्य रोजगार है, चाहे दुर्घटना हो या व्यावसायिक बीमारी भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर या बाहर अनुबंधित हो।"

(22) अधिनियम में परिभाषित 'रोजगार चोट' की परिभाषा के अवलोकन से पता चलता है कि घायल/मृत कर्मचारी को लगी चोट केवल तभी रोजगार चोट होगी जब वह दुर्घटना या किसी व्यावसायिक बीमारी के कारण हो।

बीमित व्यक्ति के रोजगार से बाहर और उसके दौरान, यदि वह किसी

यदि बीमाकृत रोजगार हो इसके अलावा यह स्पष्ट है कि चोट केवल तभी होगी जब इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में व्यक्ति को ऐसी चोट लगी हो। यदि घायल व्यक्ति को लगी चोट या घायल व्यक्ति की मृत्यु रोजगार के दायरे से बाहर होती है तो इसे रोजगार की चोट नहीं माना जा सकता है।इसलिए इस तरह की चोट पर आधारित दावा बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के आश्रितों के लिए किसी अन्य अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत उनकी पात्रता के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने के लिए अधिनियम के तहत एक बाधा नहीं होगी।कोई भी अन्य व्याख्या शब्दों को कम कर देगी।

(23) 'रोजगार क्षति' शब्द पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. निगम बनाम फ्रांसिस डी कोस्टा 4 शीर्षक वाले फैसले में विचार किया गया है। परिभाषा को स्पष्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी चोट को केवल तभी रोजगार चोट के रूप में माना जाएगा जब वह किसी दुर्घटना के कारण होती है जिसकी उत्पत्ति रोजगार में हुई थी।यह नहीं कहा जा सकता कि केवल सड़क दुर्घटना की उत्पत्ति रोजगार में हुई है।इसलिए, इस तरह की चोट को ई.

एस. आई. अधिनियम के तहत आवश्यक 'रोजगार से उत्पन्न चोट' के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'रोजगार चोट' के अर्थ को भी समझाया और कहा कि 'रोजगार के दौरान' शब्द का अर्थ केवल रोजगार की अवधि के दौरान लगी चोट होगी, अर्थात् कार्यालय के घंटों के दौरान।इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया कि भले ही कोई दुर्घटना ड्यूटी के घंटों के भीतर न हो, फिर भी चोट को नौकरी के दौरान लगी चोट ही माना जाएगा, जब वह घायल या मृतक को किसी दुर्घटना में लगी हो, जिसका उसके नौकरी से उचित और आकस्मिक संबंध हो।माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“6. हमारे निर्णय में, "रोजगार से उत्पन्न होने वाले" शब्दों का उपयोग करके, विधायिका ने "रोजगार क्षति" को एक प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया।चोट उस हद तक होनी चाहिए जिसके लिए दुर्घटना या उसके रोजगार से उत्पन्न होने वाली व्यावसायिक बीमारी को जिम्मेदार ठहराया जा सके।"इस संदर्भ में 'आउट ऑफ' का अर्थ रोजगार के कारण होना चाहिए।, बेशक, "आउट ऑफ" वाक्यांश का एक विशिष्ट अर्थ भी है।यदि किसी व्यक्ति को उसकी नौकरी से बाहर बताया जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास नौकरी नहीं है।वाक्यांश "आउट ऑफ" का दूसरा अर्थ है "प्रभावित, प्रेरित या इसके कारणःदया से; उसके प्रति सम्मान से।(वेबस्टर कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी-अंतर्राष्ट्रीय संस्करण-1984)।खंड 2 (8) के संदर्भ में, "आउट ऑफ" शब्द इंगित करते हैं कि चोट एक दुर्घटना के कारण होनी चाहिए जिसकी उत्पत्ति रोजगार में हुई थी।एक मात्र सड़क दुर्घटना, जबकि एक कर्मचारी अपने रोजगार के स्थान पर जा रहा है, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका मूल कारखाने में उसके रोजगार में है।"रोजगार के बाहर" वाक्यांश का अर्थ दक्षिण मैटलैंड रेलवे प्राइवेट लिमिटेड बनाम जेम्स के मामले में भी लगाया गया था ।

"बाहर या रोजगार" वाक्यांश का अर्थ लगाते हुए, स्टार्क, जे, ने कहा कि "के बाहर" शब्दों के लिए आवश्यक है कि चोट की उत्पत्ति रोजगार में हुई थी। "

7. जब तक कोई कर्मचारी यह स्थापित नहीं कर सकता कि चोट लगी थी या उसकी उत्पत्ति रोजगार में हुई थी, वह अधिनियम की खंड 2 (8) के आधार पर दावे में सफल

नहीं हो सकता है। शब्द "दुर्घटना" से उत्पन्न होता है उसका रोजगार इंगित करता है कि कोई भी दुर्घटना जो रोजगार के स्थान पर या रोजगार के उद्देश्य से जाने के दौरान हुई थी, उसे उसके रोजगार से उत्पन्न नहीं कहा जा सकता है। यहाँ दुर्घटना और रोजगार के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है l

8. खंड 2 की उप-खंड (8) में सीमा के अन्य शब्द "उसके नियोजन के दौरान" हैं।"पाठ्यक्रम में" का शब्दकोश अर्थ है "दौरान (समय के साथ, जैसे-जैसे समय बीतता जाता है), करते समय (द कन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, न्यू सेवेंथ एडिशन)। शब्दकोश का अर्थ इंगित करता है कि दुर्घटना अवधि या रोजगार के भीतर या उसके दौरान होनी चाहिए।यदि कर्मचारी की कार्य पारी शाम 4:30 बजे शुरू होती है, तो उस समय से पहले कोई भी दुर्घटना "उसके रोजगार के दौरान" नहीं होगी।हो सकता है कि कारखाने की यात्रा शाम 4:30 बजे कारखाने में काम करने के लिए की गई हो, लेकिन यह यात्रा निश्चित रूप से रोजगार के लिए नहीं थी।यदि कर्मचारी के कारखाने के लिए अपने घर से निकलने के क्षण से ही रोजगार शुरू हो जाता है, तो भले ही कर्मचारी अपने घर के दरवाजे पर गिर जाता है और गिर जाता है, दुर्घटना को उसके रोजगार के दौरान हुआ माना जाएगा।यह व्याख्या अर्थहीनता हो जाती है और इससे बचना चाहिए।

11. "अपने रोजगार के दौरान" वाक्यांश के अर्थ का निर्माण करते हुए, लॉर्ड डेनिंग द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि पिछले 30 वर्षों में वाक्यांश के अर्थ को धीरे-धीरे बढ़ाया गया था ताकि कुछ ऐसा करना शामिल किया जा सके जो कर्मचारी के रोजगार के लिए उचित रूप से आकस्मिक था।"यथोचित आनुषंगिक" का परीक्षण बड़ी संख्या में अंग्रेजी निर्णयों में लागू किया गया था।लेकिन लॉर्ड डेनिंग ने बताया कि उन सभी मामलों में कर्मचारी उस परिसर में था जहां वह काम करता था और विश्राम के लिए कैंटीन या अन्य स्थान पर जाने के दौरान घायल हो गया था।हालाँकि, लॉर्ड डेनिंग ने आगाह किया कि "यथोचित रूप से आकस्मिक" शब्दों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और उस तरह के मामलों तक ही सीमित होना चाहिए।लॉर्ड डेनिंग ने कहाः-

"एक ऐसा मामला लें जहाँ एक आदमी अपनी साइकिल पर या अपनी कार में अपने कार्यस्थल पर या वहाँ से जा रहा हो।हो सकता है कि वह अपनी नौकरी के लिए कुछ "उचित रूप से आकस्मिक" कर रहा हो।लेकिन अगर रास्ते में उसकी कोई दुर्घटना

होती है तो यह अच्छी तरह से तय है कि यह "उसके रोजगार से और उसके दौरान उत्पन्न नहीं होती है।"यहां तक कि अगर उसका नियोक्ता परिवहन प्रदान करता है, ताकि वह अपने नियोक्ता के वाहन में एक यात्री के रूप में काम करने जा रहा है (जो निश्चित रूप से उसके रोजगार के लिए उचित रूप से आकस्मिक है) फिर भी अगर वह किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है, तो यह अपने रोजगार से और उसके दौरान उत्पन्न नहीं होता है।इसे एक अधिनियम में एक विशेष "माननना" प्रावधान की आवश्यकता थी ताकि इसे उनके रोजगार से और उसके दौरान "माना" जा सके।

13. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की खंड 3 (1) में दिखाई देने वाले "उनके रोजगार के दौरान" शब्दों के अर्थ की इस न्यायालय द्वारा सौराष्ट्र नमक विनिर्माण कंपनी बनाम बाई वालू का मामला, राजा, ए. आई. आर 1958 एस. सी. 881 मामले में जाँच की गयी थी, वहाँ, अपीलकर्ता, एक नमक निर्माण कंपनी, ने अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के श्रमिकों को नियुक्त किया।नमक का काम पोरबंदर शहर के सामने एक खाड़ी के पास स्थित था।नमक के कार्यों तक शहर से कम से कम दो तरीकों से पहुँचा जा सकता था, एक लगभग 6 से 7 मील लंबा भूमि मार्ग और दूसरा एक खाड़ी के माध्यम से जिसे नाव द्वारा पार किया जाना था।12.6.1952 की शाम को, खराब मौसम और अधिक लोडिंग के कारण कुछ श्रमिकों को ले जा रही एक नाव पलट गई।इसके परिणामस्वरूप कुछ मजदूर डूब गए।विचार के लिए सामने आए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या दुर्घटना श्रमिकों के रोजगार के दौरान हुई थी।एस. जाफर इमाम, जे. ने अदालत के लिए बोलते हुए कहा, "एक नियम के रूप में, एक कर्मचारी का रोजगार तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि वह रोजगार के स्थान पर नहीं पहुंच जाता है और जब वह रोजगार के स्थान को छोड़ देता है, तो नौकरी के स्थान से आने-जाने की यात्रा को बाहर रखा जाता है।"सिद्धांत को व्यापक रूप से निर्धारित करने के बाद, एस. जाफर इमाम, जे., ने देखा या देखा कि इस सिद्धांत के लिए समय और स्थान दोनों में कुछ उचित विस्तार हो सकता है।एक कर्मचारी को अपने रोजगार के दौरान माना जा सकता है, भले ही वह कुछ विशेष मामलों में अपने नियोक्ता के परिसर में नहीं पहुंचा था या नहीं गया था।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की बहुत सावधानी से जांच आदेशनी होगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या दुर्घटना एक आदेशमचारी के रोजगार से और उसके दौरान हुई थी, हर समय काल्पनिक विस्तार के इस सिद्धांत को

ध्यान में रखते हुए।लेकिन, विशेष रूप से मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि कर्मचारी एक नाव का उपयोग करता था, जिसका उपयोग सार्वजनिक नौका के रूप में भी किया जाता था, जिसके लिए उन्हें नाविक के बकाया का भुगतान करना पड़ता था, एस.जाफेर इमाम, जे. ने कहाः-

"यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई कर्मचारी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक परिवहन पर होता है वह जनता के किसी अन्य सदस्य के रूप में वहाँ है और अपने रोजगार के दौरान वहाँ नहीं है जब तक कि उसके रोजगार की प्रकृति ही उसके लिए वहाँ होना आवश्यक न बना दे।एक कर्मचारी जिस क्षण से अपना घर छोड़ता है और अपने काम पर जाता है, उसी क्षण से वह अपने काम के क्रम में नहीं होता है।वह निश्चित रूप से अपने रोजगार के क्रम में है यदि वह कार्य स्थल या एक बिंदु या एक ऐसे क्षेत्र में पहुँचता है जो काल्पनिक विस्तार के सिद्धांत के भीतर आता है, जिसके बाहर नियोक्ता उसके साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।वर्तमान मामले में, भले ही यह माना जाए कि धारणा विस्तार का सिद्धांत बिंदु डी पर फैला हुआ है, सिद्धांत को इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।जिस क्षण एक कर्मचारी एक नाव या बाएं बिंदु ए में बिंदु बी छोड़ देता है, लेकिन अभी तक बिंदु बी तक नहीं पहुँचता है, उसे अपने कार्य के दौरान नहीं कहा जा सकता है और इन दो बिंदुओं के बीच की यात्रा में उसके साथ होने वाली कोई भी दुर्घटना उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हुई नहीं कही जा सकती है। श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त और उच्च न्यायालय दोनों ने यह मानने में गलती की कि इस मामले में मृत श्रमिक अभी भी अपने रोजगार के दौरान थे जब वे बिंदु ए और बी के बीच खाड़ी को पार कर रहे थे। दुर्घटना जो तब हुई जब नाव लगभग बिंदु ए पर थी जिसके परिणामस्वरूप इतने सारे श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उस दुर्घटना के लिए अपीलकर्ता को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

(24) अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत क्षति रोजगार के परिसर में नौकरी की आवश्यकताओं के निष्पादन के दौरान हुई होनी चाहिए थी या यदि वे रोजगार के परिसर के बाहर कहीं भी हुई हैं, तो वही दुर्घटना में हुई होनी चाहिए थी जिसका रोजगार से उचित और आकस्मिक संबंध है, तभी; घायल/मृतक को लगी चोट को रोजगार दुर्घटना के रूप में माना जा सकता है।

(25) हालांकि खंड 51 ई, जिसे अधिनियम में 01.06.2000 से जोड़ा गया है, यह काल्पनिक कल्पना पैदा करता है कि एक कर्मचारी के साथ उसके आवास से रोजगार के स्थान तक आने-जाने के दौरान दुर्घटना हो जाती है।

कर्तव्य के लिए नियोजन के स्थान या कर्तव्य का पालन करने के बाद नियोजन के स्थान से उसके निवास तक, यह माना जाएगा कि यह रोजगार के 'बाहर' और 'पाठ्यक्रम में' उत्पन्न हुआ है, हालांकि, यह काल्पनिक कल्पना भी इसके संदर्भ में आत्यन्तिक नहीं है।खंड स्वयं यह स्पष्ट करता है कि कर्मचारी को लगी चोट को 'रोजगार चोट' माना जाएगा, जब वह कार्यस्थल पर आता है या जाता है, केवल तभी जब रोजगार का उन परिस्थितियों, समय और स्थान के साथ संबंध है जिसमें दुर्घटना हुई थी।इसलिए यह फिर से इस मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशक, ई. एस. आई. निगम का मामला (उपर्युक्त) फैसले की ओर ले जाता है। जिसने निर्धारित किया है कि यदि कर्मचारी को परिसर और कार्य के घंटों के बाहर चोट लगी है तो ऐसी चोट का कार्य के साथ उचित और आनुषंगिक संबंध होना चाहिए।इसलिए केवल खंड 51 ई को शामिल करने से मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस दुर्घटना के दावे को बाहर नहीं किया जा सकता है जो उस समय हुई थी जब व्यक्ति कथित रूप से ड्यूटी के घंटों के बाद अपने घर जा रहा था।अधिनियम की खंड 51 ई के अवयवों को बीमा कंपनी द्वारा अधिनियम की खंड 53 को लागू करने के लिए अनुरोध और साबित करना होगा।

(26) वर्तमान मामले में, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मृतक की नौकरी की आवश्यकता के प्रदर्शन के दौरान चोट लगी थी या किसी दुर्घटना में उसे चोट लगी थी जिसका रोजगार से उचित और आकस्मिक संबंध है या उसे लगी चोट का मृतक के रोजगार से कोई उचित और आकस्मिक संबंध था या ई. एस. आई. अधिनियम के तहत दावेदार द्वारा प्राप्त लाभ मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन्हें उपलब्ध लाभों के समान हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में लगी चोट 'रोजगार की चोट' साबित हुई थी।अतः इस मामले में अधिनियम की खंड 53 लागू नहीं होती है।

(27) अन्यथा भी, इस अधिनियम के तहत 'एक कर्मचारी के रूप में' शब्द; जैसा कि अधिनियम की खंड 53 की अंतिम पंक्ति में उल्लेख किया गया है, का भी कोई महत्व नहीं

है।इन शब्दों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं और से मुआवजे का दावा करने के खिलाफ प्रतिबंध केवल तभी माना जाता है जब घायल/मृतक को इस अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में चोटें लगी हों। इससे पता चलेगा कि अधिनियम की खंड 53 द्वारा बनाया गया प्रतिबंध केवल किसी अन्य बाद के मुआवजे के संबंध में होगा, यदि घायल या आश्रितों द्वारा दावा किया जाता है; ई. एस. आई. अधिनियम के तहत एक कर्मचारी होने के नाते घायल/मृतक की क्षमता में। इसका मतलब यह होगा कि यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा नहीं है जिसे अधिनियम की खंड 53 द्वारा बाहर रखा जाएगा, बल्कि यह ई. एस. आई. अधिनियम के तहत परिभाषित कर्मचारियों के लिए समान मुआवजे के प्रावधान वाले किसी अन्य अधिनियम के तहत कोई अन्य मुआवजा, यदि दावा किया जाता है। इसका मतलब है कि अधिनियम की खंड 53 केवल किसी अन्य श्रम कानून के तहत नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति से मुआवजे की प्राप्ति पर रोक लगाती है जो कर्मचारियों/श्रमिकों को मुआवजा प्रदान कर सकता है।यह अधिनियम की खंड 61 के प्रावधान द्वारा भी स्पष्ट किया गया है; जो विशेष रूप से कहता है कि एक बार किसी व्यक्ति को ई. एस. आई. अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किया जाता है, तो वह किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य किसी भी 'समान लाभ' को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।अधिनियम की खंड 53 के प्रावधानों की कोई अन्य अप्रतिबंधित व्याख्या करने से अधिनियम की खंड 61 अनावश्यक हो जाएगी।और यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधायिका को कानून की किसी भी खंड में व्यर्थ के शब्द नहीं माना जा सकता है, ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 61 की तरह कानून की पूरी खंड को बर्बाद करने की बात करना बहुत कम है। इसलिए अधिनियम की खंड 61 के साथ पढ़ें, खंड 53 की व्याख्या नियोक्ता से या ई. एस. आई. अधिनियम के तहत एक कर्मचारी के रूप में अपनी क्षमता में ऐसे घायल व्यक्ति/आश्रित को क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक किसी भी व्यक्ति से कर्मचारी के रूप में अपनी क्षमता में समान मुआवजे के केवल दूसरे दावे को प्रतिबंधित करने के लिए की जा सकती है। चूँकि मोटर वाहन अधिनियम और ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध लाभों के बीच कोई समानता नहीं है, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को मुआवजे से इनकार करने के लिए दो अधिनियमों के प्रावधानों को मिलाया नहीं जा सकता है। किसी मामले में, मोटर वाहन

अधिनियम के तहत दी गई राशि पर अर्जित मासिक ब्याज भी ईएसआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध लाभों की कुल राशि से कई गुना अधिक हो सकता है। इसलिए इन दोनों अधिनियमों के तहत उपलब्ध लाभ पूरी तरह से अलग और अलग हैं।

(28) इस पहलू पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने 2013 का संख्या 881 में शीर्षक के रूप में अमरजीत कौर और अन्य बनाम संजीव पाठक और अन्य जो 23.08.2017 को निर्णय हुआ, पर निर्णय लेने वाले अन्य लोगों का मानना है कि ई. एस. आई. अधिनियम के तहत आश्रितों को उपलब्ध लाभ उनके दायरे, मात्रा, निरंतरता, दृढ़ता और यहां तक कि पात्रता और उपलब्धता में भी सीमित हैं।इसलिए, केवल इसलिए कि किसी कर्मचारी को ईएसआई अधिनियम के तहत लाभ दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है। निर्णय के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः-

"10. क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए दावेदारों को अयोग्य ठहराने के लिए दो प्रावधानों को क्यों नहीं मिलाया जा सकता है, इसका एक अन्य कारण है-इन दो प्रावधानों के तहत दिए गए लाभों/मुआवजे/अनुमेय की प्रकृति।कर्मचारी राज्य के तहत बीमा अधिनियम, बीमित व्यक्ति या उसके आश्रित केवल अधिनियम या नियमों या उसके तहत बनाई गई योजना के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट मुआवजे या लाभों के हकदार हैं।दूसरी ओर, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावेदार मृतक की मृत्यु के कारण वास्तव में हुए या उनके द्वारा साबित किए गए कुल नुकसान के मुआवजे के हकदार हैं।इसलिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाभों की प्रकृति और मात्रा पूरी तरह से अलग हैं।मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कुछ लाभ उपलब्ध हैं, जिनकी कल्पना या विचार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम द्वारा भी नहीं किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम द्वारा प्रेम और स्नेह और संघ के नुकसान के कारण मुआवजे के कारण होने वाले नुकसान पर विचार भी नहीं किया गया है, आश्रितों को दिए जाने वाले लाभ अंतिम रूप से प्राप्त नहीं होते हैं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत समीक्षा/परिवर्तन के अधीन रहते हैं। खंड

(क) अधिनियम में आश्रितों को लाभों की समीक्षा का प्रावधान है।इस खंड के अनुसार, लाभ निगम की संतुष्टि के अनुसार समीक्षा के अधीन हैं, यहां तक कि किसी भी मृत्यु या जन्म या विवाह या पुनर्विवाह या दुर्बलता की समाप्ति या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के मामले में भी।इसलिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभ आकस्मिक लाभों की प्रकृति में हैं, जो अधिनियम के प्रावधानों में उल्लिखित कुछ शर्तों की पूर्ति के संबंध में अधिकारियों द्वारा उनकी संतुष्टि के अनुसार किसी भी समय परिवर्तन के अधीन हैं। दूसरी ओर, मोटर वाहन दुर्घटना में मरने वाले मृतक के आश्रितों के लिए उपलब्ध मुआवजा/लाभ आत्यन्तिक और एक बार का भुगतान है। आत्यन्तिक और आत्यन्तिक पैमाने पर मुआवजे की किसी भी पात्रता को किसी भी प्रतिबंधित लाभ के अनुदान से बाहर नहीं किया जा सकता है; जो अन्यथा समय-समय पर परिवर्तन के अधीन भी हैं।इसलिए, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को मृतक के आश्रितों के लाभों की पात्रता के साथ मिलाने और मिलाने का प्रयास पूरी तरह से गलत है और यह किसी भी कानूनी रूप से टिकाऊ आधार के बिना है।

11. अन्यथा भी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक सामाजिक लाभकारी कानून है। इसलिए, इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि बीमित व्यक्ति के रोजगार के बाहर होने वाली चोट या मृत्यु के कारण बीमित व्यक्ति या उसके आश्रितों को उपलब्ध अन्य लाभों को प्रतिबंधित किया जाए।कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की खंड 53 की व्याख्या किसी अन्य वैधानिक श्रम कानून के तहत एक कर्मचारी या उसके आश्रितों के रूप में कर्मचारी को उपलब्ध अन्य 'वैधानिक मुआवजे' को प्रतिबंधित करने के लिए की जा सकती है, जिसमें बीमित व्यक्ति को लगी चोटों के संबंध में या बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण आश्रितों की पात्रता के संबंध में कुछ सामान्य सुरक्षा हो सकती है।"

(29) मोटर वाहन अधिनियम की खंड 167 में निहित प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि विधायिका ने कभी भी ई. एस. आई. अधिनियम के तहत उपलब्ध मुआवजे को मोटर वाहन अधिनियम के तहत उपलब्ध मुआवजे के साथ तुलनीय या बहिष्कृत नहीं माना। इस खंड ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत उपलब्ध मुआवजे के विकल्प के रूप में श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत एक मुआवजा उपलब्ध कराया

है; यह निर्धारित करके कि कोई व्यक्ति इन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के तहत मुआवजे का दावा कर सकता है, न कि इन दोनों अधिनियमों के तहत, निश्चित रूप से यह विकल्प किसी व्यक्ति पर भी लागू होता है जो एक कर्मचारी या कर्मचारी के रूप में अपनी क्षमता में श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत और जब वह अपने नियोक्ता से मुआवजे का दावा करता है।इससे पता चलता है कि हालांकि विधायिका ने श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत देय मुआवजे को मोटर वाहन अधिनियम के तहत उपलब्ध मुआवजे के साथ तुलनीय माना, लेकिन ईएसआई अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों को विधायिका द्वारा वैकल्पिक मुआवजे के स्तर तक नहीं बढ़ाया गया है।इसलिए ई. एस. आई. अधिनियम के तहत भुगतान किया गया कोई भी मुआवजा मोटर वाहन अधिनियम के तहत देय मुआवजे का विकल्प नहीं होगा। ये एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध दो अलग-अलग और स्वतंत्र उपचार होंगे।

(30) ई. एस. आई. अधिनियम के तहत दावेदार द्वारा प्राप्त किए जा रहे आवधिक लाभ के कारण मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा याचिका के प्रतिबंध के खिलाफ जाने वाला एक अन्य पहलू यह है कि आश्रितों को उपलब्ध आवधिक भुगतान केवल पारिवारिक पेंशन की प्रकृति में है।यह मृतक के आश्रितों के लिए अधिनियम के तहत उनके अपने अधिकार में उपलब्ध है।लाल देई और मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय बनाम हिमाचल सड़क परिवहन 5 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक के आश्रितों द्वारा प्राप्त की जा रही पारिवारिक पेंशन को निर्भरता के नुकसान की गणना करते समय मृतक की आय से नहीं काटा जाना चाहिए।चूँकि मृतक के आश्रितों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने पर भी कोई रोक नहीं है, इसलिए दुर्घटना से उत्पन्न दावे के खिलाफ इसी तरह के किसी अन्य आवधिक भुगतान पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ई. एस. आई. अधिनियम के मामले में, आश्रितों को जो कुछ भी मिल रहा है, वह आंशिक रूप से कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान किए गए योगदान और आंशिक रूप से नियोक्ता के योगदान का एक उत्पाद है।इसलिए, मृत कर्मचारी के नियोक्ता को रोजगार क्षति से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के तहत कोई भी भुगतान करने के किसी भी दायित्व से मुक्त किया जा सकता है; एक कर्मचारी के रूप में मृतक की पात्रता के लिए, हालांकि, ऐसा आवधिक

भुगतान, जो पारिवारिक पेंशन की प्रकृति में है, किसी अन्य अधिनियम के तहत बनाए गए अपने स्वतंत्र दायित्व का निर्वहन करने से रोजगार के लिए किसी अजनबी को मुक्त नहीं करेगा।यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में फिर से लागू किया गया है जबकि वर्ष 1948 का ई. एस. आई. अधिनियम।इसके बावजूद मोटर वाहन अधिनियम में विधायिका द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में उल्लंघन करने वाले वाहन के बीमाकर्ता के दायित्व को विशेष रूप से बाहर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है; यदि कर्मचारी के आश्रितों को ईएसआई अधिनियम के तहत मुआवजा या लाभ मिल रहे हैं (कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे के विपरीत) मृतक के कर्मचारी होने की क्षमता में।न तो मोटर वाहन अधिनियम की खंड 166 ने ऐसे व्यक्ति द्वारा दावा याचिका दायर करने के खिलाफ कोई रोक लगाई है और न ही इसे बीमा कंपनी के लिए अधिनियम की खंड 149 के तहत कोई बचाव किया गया है।विधायिका की इस चूक को जानबूझकर लिया जाना चाहिए क्योंकि विधान बनाने में चूक को हमेशा विधायिका की ओर से जानबूझकर माना जाता है।इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि कर्मचारी के आश्रितों को ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कुछ लाभ हो सकते हैं क्योंकि मृतक एक कर्मचारी है, उन्हें उक्त दुर्घटना के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने से नहीं रोका जाएगा।

(31) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यानी हमीदा खातून के मामले (ऊपर) द्वारा भरोसा किया गया निर्णय अपीलकर्ता के मामले का समर्थन नहीं करता है।इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि यह निर्णय श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 से संबंधित कानून की चर्चा पर आधारित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध मुआवजे को स्पष्ट रूप से मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावेदारों को उपलब्ध मुआवजे का विकल्प बनाया गया है। इसलिए, इस निर्णय ने दावा याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं माना।बल्कि इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की खंड 53 ध्यान दें में रखते हुए मुआवजे पर फिर से काम करने के लिए केवल संबंधित एम. ए. सी. टी. को मामला वापस भेज दिया।

(32) जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा है कि राष्ट्रीय बीमा कंपनी (उपरोक्त) के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की

संभावनाओं के प्रतिशत को कम करने के कारण मुआवजे की राशि को कम करना होगा, वही स्वीकार करने योग्य है।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 50 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाओं को जोड़ा है।हालांकि, उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 50 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति के मामले में 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाएं लागू होंगी।तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि दावेदार न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 50 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत तक भविष्य की संभावनाओं के लाभ के हकदार होंगे।तदनुसार, निर्भरता के नुकसान के कारण दावेदारों को दिए गए मुआवजे पर फिर से काम करने की आवश्यकता है।अतः, निर्भरता का नुकसान रु० 9000/- + 3600 (9000 का 40 प्रतिशत) = रु० 12,600-6300 (12,600 का 50 प्रतिशत) = रु० 6300/- 1 जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, हालांकि ई. एस. आई. अधिकारियों द्वारा दावेदार को दी गई पारिवारिक पेंशन का लाभ इस मामले में कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, हालाँकि, चूंकि दावेदार ने वर्तमान मामले में कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए न्यायाधिकरण के निष्कर्षों में मृतक की आय से आवधिक भुगतान की कटौती को अंतिम रूप दिया गया है।अतः निर्धारित आय में से रु० महीने के लिए 2403/- की कटौती की जानी चाहिए जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा किया गया था।तदनुसार दावेदार को मासिक नुकसान रु० 3,897/- (6300-2403)। यह रु० 3900/- प्रति माह तक पूर्णांक है 1

(33) नतीजतन, दावेदार को रुपये के मुआवजे का हकदार माना जाता है। 8,57,400- नीचे दिए गए विवरण के अनुसारः

क्र. सं	मद	राशि (रु.)
1	निर्भरता का वार्षिक नुकसान	3900 x 12 = 46,800/-
2	गुणक 18	46,800 x 18 = 8,42,400 -
3	अंतिम संस्कार का खर्च	15,000/-

	कुल	8,57,400/-

(34) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा आगे कोई तर्क नहीं दिया गया 1

(35) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गुड़गांव के निर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

पायल मेहता

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

महीपाल
3D1604
ट्रांसलेटर